

**कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन-834002, Email: pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक:- 463 दिनांक:- 02/05/2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- मेसर्स नार्थ कर्णपूरा ट्रान्सको लि० द्वारा चतरा जिला अंतर्गत नार्थ कर्णपूरा (टंडवा) से गया तक 400 के०भी० डी०सी० ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 197.0115 हे० (चतरा उत्तरी-61.772 हे०, चतरा दक्षिणी-119.8806 एवं लातेहार-15.3589 हे०) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन विभागीय पत्रांक 894 दिनांक 10.03.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयक परियोजना मेसर्स नार्थ कर्णपूरा ट्रान्सको लिमिटेड द्वारा चतरा जिला अन्तर्गत नार्थ करणपुरा (टंडवा) से गया तक 400 के०भी० डी०सी० ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 197.0115 हे० वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय राँची का पत्र संख्या-FP/JH/TRANS/41236/2019/964 दिनांक 07.03.2023 द्वारा पांच बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है।

भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय राँची द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू के पत्रांक 742 दिनांक 19.04.2023 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 1075 दिनांक 26.04.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय में समर्पित किया गया है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू एवं हजारीबाग के प्रतिवेदनानुसार भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय राँची द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन बिन्दुवार निम्नवत है-

क्र०सं	पृच्छाए	निराकरण
i	The proposal apparently involves violation over GMJJ land, which is neither under jurisdiction nor under management/ownership of State Forest Department. Revenue Department of Jharkhand has jurisdiction over such land, however, JJ land falls under deemed forest category. Therefore, either such land violation be compounded appropriately by State Government before forwarding the proposal to central government or should clearly specify the penal provisions to be undertaken along with recommendation of the department having jurisdiction in the land.	<p>क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू एवं हजारीबाग द्वारा सूचित किया गया है कि</p> <p>“Chatra South Division - The user agency has informed that one tower {Base area (16mx16m) is 0.0256 ha.} in plot no. 973, Village Kasiyatu, Block Simariya, District Chatra, which was erected unintentionally based on the authenticated land schedule report provided to them by the concerned Circle Office.</p> <p>Also, the user agency informed that Plot no. 973, Village Kasiyatu which was initially categorized as “Gair Majrua” vide CO letter no 464 dated 08.07.2019 and later the nature of land changed from Gair Majarua to Jungle Jhari as per revised CO report vide letter no. 621 dated 14.09.2021.</p> <p>User agency agrees for any dispensation given by the REC / State Forest dept. on the aforesaid issue which shall be complied by the NKTL.</p>

		<p>The user agency has unintentionally violated the FC Act. The user agency have erected one tower on 0.0256 ha of plot no. 973 of Kasiyatu village which is GMJJ land as per government records . No other violation apart from this had been done by the user agency. As the user agency has violated the FC Act. Therefore Penal CA & Penal NPV may be imposed on the user agency.</p> <p>For Chatra North Division - No such violation over GMJJ/Forest land has been found.</p> <p>For Latehar Division- No such violation over GMJJ/Forest land has been found."</p>
ii	The Committee opined that a detailed report in the may be submitted by the State Forest Department regarding the extant proposition.	<p>क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू एवं हजारीबाग द्वारा सूचित किया गया है कि</p> <p>"Chatra South Division - The user agency has erected one tower on plot no. 973 of village Kasiyatu. Which is GMJJ land as per government record. No other violation has been done by M/S NKTL.</p> <p>For Chatra North Division - No such violation of FCA 1980 has been found.</p> <p>For Latehar Division- No such violation of FCA 1980 has been found."</p>
iii	The Committee opined, if user agency started work on GMJJ while the FC proposal is still at processing level, the FC violation should be dealt as per FC Handbook's para 1.21 (ii) a & b only, whereas the Penal CA DFL area should have been 10 times of the area involved in the proposal with 5 times of NPV with regular NPV rates.	<p>क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू एवं हजारीबाग द्वारा सूचित किया गया है कि</p> <p>"Chatra South Division - The user agency has violated the FC Act by erecting one tower on plot no. 973 of village Kasiyatu which is a GM Jungle Jhari Land. Therefore, penal CA DFL area of 10 times of the violated area involved in the proposal along with 5 times of NPV rate may be imposed on the user agency.</p> <p>For Chatra North Division - No such violation of FCA 1980 has been found.</p> <p>For Latehar Division- No such violation of FCA 1980 has been found."</p>
iv	The Committee raised a question over employment generation and suggested UA to submit the DPR/ Report prepared in the proposal to justify/clarify it.	Employment generation report given by the user agency may be accepted. as Annexure-1.
v	Wildlife Management Plan, soil and moisture conservation plan with approval of Chief Wildlife Warden to be submitted before the final approval.	Undertaking for Wildlife Management & Soil Conservation Plan submitted by user agency as Annexure-2.

02.05.2023

उपरोक्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित वनभूमि के मौजा-कसियातु प्लॉट नं० 973 के जंगल-झाड़ी वनभूमि (GM-JJ Land) पर FC. Act. का उल्लंघन किया गया है। भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय राँची के पत्रांक 964 दिनांक 07.03.2023 द्वारा संसूचित REC की 59वीं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में कंडिका सं० iii में उक्त उल्लंघन के कारण अधिरोपित शर्तों के आलोक में विषयगत परियोजना प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई की जा सकती है।


क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू एवं हजारीबाग से प्राप्त भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय राँची द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन की तीन-तीन प्रतियाँ तीनों वन प्रमंडलों से इस पत्र के साथ भेजते हुए अनुरोध है कि निराकरण प्रतिवेदन से भारत सरकार को अवगत कराते हुये इस परियोजना हेतु कुल 197.0115 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज-I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं HoFF, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।


अनु०:—यथोक्त।

निराकरण प्रतिवेदन तीन-तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन

 02.05.2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।


2.5.23